(ग) पड़ोसी राज्यों को किन किन दुग्ध एजेंसियों से केन्द्रीय सरकार दूध खरीदती है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार दूध की उक्त मात्रा की खरीद के लिए प्रति वर्ष कितनी धनराशि अदा करती है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (घ) 1988-89 के दौरान डेरी संघों से दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेरी, दिल्ली द्वारा खरीदे गए दूध के ब्यौरे और किए गए भुगतान को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(मात्रा लाख कि० ग्रा० में)
(लाख रुपये में)

क्र० सं०	राज्य संघ	दिल्ली दुग्ध योजना		मदर डेरी		
		मात्रा (कि० ग्रा०)	राशि (रुपये)	मात्रा (कि० ग्रा०)	राशि (रुपये)	
1	उत्तर प्रदेश	44	255	140		
2	राजस्थान	78	406	181		
3	पंजाब	23	119	139		
						3765
4	मध्य प्रदेश	42	205	46		
5	हरियाणा	3	16	2		
7	गुजरात	—	—	258		

मध्य प्रदेश में खेती लायक भूमि पर खेती न किया जाना

503. **श्री हरि सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में उपलब्ध खेती लायक अधिकांश भूमि पर खेती नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार उस भूमि पर खेती आरंभ करने के लिए क्या उपाय कर रही है?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकार द्वारा प्राप्त किये गए दूध का भुगतान

504. **श्री हरि सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूध की कीमतों में वृद्धि के कारण केन्द्रीय सरकार ने बढ़ी हुई कीमतों के आधार पर 1988-89 में प्राप्त किये गए दूध की बकाया राशि का भुगतान किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कितनी राशि का आकलन किया गया है तथा बढ़ी हुई कीमतों के आधार पर बकाया राशि प्राप्त करने वाले कौन-कौन हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव): (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Modernisation of steel **plant under** SAIL

505. SHRI KAHNU CHARAN LENKA: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) the progress made so far in regard to modernisation of the steel plant under the Steel Authority of India Limited;

(b) the time by when the modernisation of each plant is likely to be completed, and the estimated expenditure thereon; and

(c) the estimated increase in production and productivity as a result thereon?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR): (a) to (c) The present position in regard to the modernisation projects of the steel plants of the Steel Authority of India Limited is annexed *(See* Appendix CLI, Annexure No. 36)

National Commission on bonded labourers

506. SHRI KAHNU CHARAN LENKA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration for undertaking an All India survey to identify the number of bonded labour in the country and for setting up a National Commission on bonded labour;

(b) if so, the decision of Goverment thereon; and

(c) the number of bonded labourers so far rehabilitated in Orrisa till date and the amount; spent for their rehabilitation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RADHAKRISHAN MALAVIYA): (a) and (b) No Sir. The Government had set up a National Commission on Rural Labour in August, 1987. The Commission have set up study groups on various subjects concerning rural labour. The terms of reference of the Study Group on 'Bonded Labour' inter-alia includes 'Studying the magnitude of the problem of bonded labour in the country'.

(c) According to he latest report received from the State Government of Orissa, out of a total number of 49,339 bonded labourers identified and freed in the State, 44,755 had been rehabilitated by 31st May, 1989. An amount of Rs. 786.82 lakhs has been released to the State Government of Orissa till date as the Central share under the Centrally Sponsored Plan Scheme for rehabilitation of Bonded Labour..

Assistance **for completion of drought relief works in Orissa**

507. SHRI KAHNU CHARAN LENKA : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether a number of productive schemes undertaken in Orissa under drought relief programme are lying incomplete due to paucity of funds; and

(b) if so, the assistance proposed to be given by the Union Government to get these works completed ?